(c) by when Government envisage spreading communications network to the farthest nook and corner of the country; and

(d) whether some foreign companies have agreed to jointly or privately coming in the field; if so, the details thereof, with their names and the states in which these intend to operate?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) State-wise target for release of telephone connections is still to be worked out; but the total connections to be released is 14 lakhs by March, 95.

(c) As per 8th Plan objective the waiting period for telephone connection is not to exceed two years in large telephone system and telephone practically on demand in rural/tribal areas by the end of 8th plan period (92—97). The expansion of Exchanges are being planned accordingly to meet the above objective. For telephone facility to all gram panchayats, the tentative target is by 1.4.95 and also additional 1.5 lakh villaesg to have LDPTS by 1.4.97.

(d) Some proposal from Foreign and Private companies have been received but no decision has been taken by the Government on this.

पूछताछ कक्ष (टेलीफोन नं. 197) को ध्वनि-रोधी बनाने का प्रस्ताव

2575. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरभाष केंद्र पूछताछ का (टेलीफोन नं. 197) को ध्वनि-रोधी बनाने पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार टेलीफोन नं. 197 पर दूरभाष के दौरान सुनाई देने वाली असम्बद्ध बातों से पूछताछ करने वाले को मुक्त रखने के लिए क्या कदम उठा रही है क्योंकि उन्हीं असम्बद्ध बातों के कारण बहुधा सही जानकारी प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) (i) सभी बड़ी प्रणालियों अर्थात् मैट्रो और मेजर नगरों में फील्ड यूनिटों द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से शोर कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं और जहां टेलीफो न आपरेटर बैठते हैं उन होंलों को वातानु कूलित बनाया जा रहा है जिससे बाहर का शोर स्वत: कम हो जाएगा ।

(ii) चूंकि इनक्वाइरी कक्ष (197) में अनेक टेलीफोन आपरेटर बैठते हैं, निकटवर्ती पीजीशनों के शोर से नहीं बचा जा सकता ।

टेलीफोन बिलों का समय पर प्राप्त न होना

2576. **श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टेलीफोन उपभोक्ताओं को समय पर टेलीफोन बिल नहीं मिलते हैं और कभी-कभी उन्हें बिल मिलते ही नहीं, ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दिल्ली टेलीफोन प्रति-माह 3.5 लाख बिल डाक से भेजता है। ऐसी कुछ घटनायें हुई हैं जिसमें उपभोक्ताओं । बिल न प्राप्त होने अथवा विलंब से प्राप्त होने की शिकायतें की हैं।